

Problem of Indian Emigrants working abroad

3189. SHRI G.Y. KRISHNAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether some cases of dispute between Indian emigrants and their foreign employers have come to the notice of Government and taken up by the Indian Missions abroad;

(b) if so, the details regarding such cases during last two years and how far success in such cases have been obtained; and

(c) whether the Missions/posts have adequate India based or local staff to look after the problems of the Indian emigrants Working abroad?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) and (b). Yes, Sir. Approximately 10493 cases of disputes between the Indian emigrants and their foreign employers have been taken up by the Indian missions/posts with the local administration/judicial authorities during 1980 and 1981. The Indian missions/posts abroad have so far met with success in a majority of these cases.

These cases are mainly regarding non-payment of agreed salaries; substitution/withdrawal of employment contracts. non-fulfilment of agreed facilities/terms and conditions; poor living conditions; non-payment of terminal benefits; harassment by employers; development on duties other than those for which recruited.

(c) The strength of our missions/posts abroad is kept under constant review by the Foreign Service Inspectorate, in keeping with the requirements of overall functional efficiency economy and objective formulae evolved by the Work Study Unit.

सीकरी समिति की रेल दुर्घटनाओं के बारे में सिफारिशें

310. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीकरी समिति ने रेल दुर्घटनाओं के संबंध में कितनी सिफारिशों की तथा सरकार ने उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं, और अस्वीकार की गई सिफारिशों के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ख) ये सिफारिशें दुर्घटनाएं रोकने में कहां तक सफल हुई हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) सीकरी समिति ने अपनी रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की थी। भाग-I में 170 अभ्युक्तियां/सिफारिशें थीं और भाग-II में 413 अभ्युक्तियां/सिफारिशें थीं। जबकि रिपोर्ट के भाग-II में शामिल सिफारिशों पर 'सरकार के दृष्टिकोण' को अन्तिम रूप दिया जा रहा है वहीं भाग-I में की गई 109 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। शेष 61 मदों में से, 52 में केवल अभ्युक्तियां थीं जिन पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी। तीन सिफारिशों की मंजूरी नहीं किया गया और 6 विचाराधीन हैं।

(ख) सीकरी समिति ने रेल संचालन में संरक्षा व्यवस्था को लागू किये जाने के बारे में एक पृथक और सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है और अनेक उपायों की सिफारिश की है जिनके कार्यान्वयन से गाड़ी परिचालन की संरक्षा में निःसंदेह सुधार आयेगा।

Central Law to Enforce Prohibition on Uniform Basis in the Country

3191. DR. KRUPASINDHU BHOI : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether India has told the World Health Organisation that despite a set of guidelines drawn up by